



नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com



रक्षा निर्यात
पहली बार अभूतपूर्व
बुलंदी पर पहुंचा
राष्ट्रीय-10

केजरीवाल ने आबकारी नीति केस में दो आप मंत्रियों का लिया नाम: ईडी

राजेश कुमार | नई दिल्ली

दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आबकारी नीति मामले में आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर दोनों का नाम लिया है। केजरीवाल को सोमवार को अदालत ने 15 दिन के लिए 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एसजीओ) एसवी राजू ने सोमवार को राज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया, केजरीवाल ने बताया है कि विवादस्पद बिचौलिया विजय नायर ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट की थी, उन्हें नहीं। एसजीओ राजू ने अदालत में कहा, अरविंद केजरीवाल का आचरण पूरी तरह से असहयोगात्मक रहा है और उन्होंने पूछताछ को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि विजय नायर मुझे



फाइल फोटो/रंजन किंगरी

नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड साझा नहीं कर रहे हैं। अदालत ने पूछा, ये तर्क न्यायिक हिरासत के आवेदन के लिए कहाँ तक ? प्रासंगिक हैं। एसजीओ ने जवाब दिया, हम बाद के चरण में उनकी ईडी हिरासत की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। सोमवार को केजरीवाल की पत्नी सुनीता और पार्टी सहयोगियों और

आप विधायक आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय कोर्ट रूम के अंदर थे न्यायाधीश कावेरी बावेजा की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में 55 वर्षीय केजरीवाल, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में

कहा कि केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने गोलमोल जवाब दिए और जानकारी छिपाई। इसमें कहा गया है कि नौ दिनों के अवधि में मुख्यमंत्री के बयान लिए गए और उनका विभिन्न गवाहों, अनुमोदकों और अन्य सह-अभियुक्तों के बयानों से सामना कराया गया। याचिका में केजरीवाल द्वारा दिए गए गोलमोल और भ्रामक उत्तरों के कुछ स्पष्ट उदाहरण सूचीबद्ध

किए गए हैं। इसमें कहा गया, उन्होंने (केजरीवाल) कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और नायर के साथ उनकी बातचीत सीमित थी। विजय नायर मुंबई स्थित मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउंडर (ओएमएल) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे। उन्होंने 2020 के दिल्ली राज्य विधान सभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के अंशकालिक स्वयंसेवक के रूप में काम किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पार्टी कार्यक्रम आयोजित करने और सोशल मीडिया हैंडल प्रबंधित करने में मदद की थी। रिमांड आवेदन में कहा गया है कि हालांकि, नायर के बयानों से पता चला है कि वह एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में रहता था और मुख्यमंत्री के कैफे कार्यालय से काम करता था। गिरफ्तार व्यक्ति को यह समझने के लिए भी कहा गया था कि जो व्यक्ति आप के अन्य नेताओं को रिपोर्ट करता था, वह आपके कैफे कार्यालय से काम क्यों करेगा, (शेष पेज 9)

कर मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत

पीटीआई | नई दिल्ली

आयकर विभाग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपए के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायमूर्ति बी वी नागरला और न्यायमूर्ति अंगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने कहा, इस आवेदन पर सुनवाई की शुरुआत में, प्रतिवादी विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मार्च 2024 के महीने में कई तारीखों पर अपीलकर्ता के खिलाफ लगभग 3,500 करोड़ रुपए की मांग की गई है।



अभिषेक सिंघवी ने इस खब की सराहना करते हुए कहा कि अलग-अलग वर्ष के लिए सारे मांग नोटिस फरवरी और मार्च में जारी किए गए जो कुल 3500 करोड़ रुपए के थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत कम ही निश्चय रहता हूँ। लेकिन मेरे जानकारी मित्र के हस्तक्षेप से मैं निश्चय रह गया हूँ। कृपया इसे जुलाई में लें। शुरुआत में, मेहता ने कहा, याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल है। 2016 के फैसले के आधार पर, जिसे चुनौती दी गई है, हमने 1700 करोड़ रुपए की मांग उठाई है। चूंकि चुनाव चल रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी पार्टी के लिए कोई समस्या पैदा हो, इसलिए चुनाव के बाद मामले की सुनवाई होने तक हम 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला 23 मार्च 2016 का है और उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर 2021 में पार्टी के खिलाफ कर की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को इस मुद्दे के गुण-दोषों पर बहुत कुछ कहना है और वे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर मुख्य याचिका का जवाब देना चाहेंगे। न्यायमूर्ति नागरला ने मेहता से पूछा कि क्या याचिका में विषय के रूप में मांग नोटिस थे। मेहता ने नहीं में जवाब दिया। कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपए के कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपए के कर की मांग की जा चुकी है। पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए हैं।



भारतीयों के लिए वीजा प्रतीक्षा समय कम करेगा अमेरिका

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को रेखांकित करते हुए नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सैटी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने उन्हें वीजा समय कम करने के लिए कहा था। यह दावा करते हुए कि यह पहली बार था कि किसी राजदूत को किसी देश में इस तरह का निर्देश दिया गया था। गार्सैटी ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीन कार्ड बैकलॉग मुद्दे का एक हिस्सा एक विधायी मामला है जिसे कांग्रेस को संबोधित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिक वीजा पर निर्णय करने से प्रतीक्षा समय 75 फीसदी कम हो गया है। गार्सैटी ने कहा, यह एक विधायी मुद्दा है जिससे कांग्रेस को निपटने की जरूरत है, चाहे वह वैध आपवासियों की संख्या हो, ग्रीन कार्ड हो, या नागरिकता हो। किसी भी

देश की तरह, सीमाएं हैं। यह भारतीयों के लिए निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि कई लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। पिछले साल, भारत में छत्र वीजा की संख्या सबसे अधिक थी, जो दूसरे सबसे बड़े से दोगुना है। उन्होंने आगे कहा, हमने केवल एक साल में भारत में वीजा निर्णयों में 60 फीसदी की वृद्धि की है, समान कर्मचारियों को बनाए रखा है और प्रतीक्षा समय को 75 फीसदी तक कम किया है। कांग्रेस को इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। 75 फीसदी कटौती के बावजूद 250 दिन की प्रतीक्षा अवधि के बारे में पूछे जाने पर, गार्सैटी ने जवाब दिया, 250 दिन अभी भी बहुत लंबा है। राष्ट्रपति ने मुझसे भारत में वीजा प्रतीक्षा समय कम करने के लिए कहा था। मेरा मानना ? है कि यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है किसी भी देश में (शेष पेज 9)

वजीराबाद में घुसा तेंदुआ, आट को किया जख्मी

सौम्या शुक्ला | नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के वजीराबाद इलाके में दिन के उजाले में एक तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई और सोमवार सुबह कम से कम आठ लोगों को घायल कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, तेंदुआ सुबह-सुबह जगतपुर गांव में एक घर की छत से कूद गया था और अगली इमारत में घुस गया जहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में कुछ लोगों द्वारा तेंदुए का पीछा करते हुए और अन्य लोगों को दहशत में भागते हुए दिखाया गया है। तेंदुए ने आठ लोगों पर हमला किया जिनकी पहचान गांव के रहने वाले महेंद्र, आकाश, नितिन, पंकज, नासिर, विपिन, सतीश और निशु के रूप में हुई है। दिल्ली फायर सर्विसेस के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि तेंदुए को बाद में पकड़ लिया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, घटना की जानकारी सुबह करीब 6.20 बजे मिली और दो दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, स्थानीय लोगों की मदद से अधिकारियों ने तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया। घायलों को अस्पताल भेजा गया। एक निवासी ने कहा कि तेंदुए को पहली बार सुबह 4.30 बजे देखा गया और 5.15 बजे पीसीआर कॉल की गई।



वजीराबाद में सोमवार को एक घर में घुसे तेंदुए को वन विभाग कर्मचारियों ने पकड़ लिया। फोटो: रंजन किंगरी/पायनियर

उन्होंने कहा, इसने एक दर्जन से अधिक लोगों पर हमला करने की कोशिश की और उनमें से कुछ को घायल कर दिया। पुलिस उपअधिका (उत्तर) एमके मोना ने कहा कि जगतपुर गांव से एक घर में तेंदुए के घुसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। मौके पर वन टीम के सात लोग और अग्निशमन विभाग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया गया और बाद में उसे इलाके से रेस्क्यू कर लिया गया। एक स्थानीय

निवासी ने कहा कि गांव जंगल से घिरा हुआ है लेकिन वहां कोई बाड़ या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा नहीं है। हाल ही में पिछले साल 1 दिसंबर को दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म में एक तेंदुआ देखा गया था। इसे आखिरी बार 6 दिसंबर को देखा गया था और वन विभाग को संदेह था कि यह असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में लौट आया है। एक हफ्ते बाद, उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में खाटूरयाम मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक कार की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई थी।



लोस चुनाव के दौरान झेलने पड़ सकते हैं लू के थपड़े

अर्चना ज्योति | नई दिल्ली

भारत अपने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाला है। वहीं भारतीय मौरस विभाग (आईएमडी) के अनुसार मतदाताओं और राजनीतिक दलों को अत्यधिक गर्मी से निपटने में कठिनाई हो सकती है। आईएमडी ने अप्रैल से जून की अवधि के दौरान उच्च तापमान की अनुमानित गंभीरता के बारे में सोमवार को चेतावनी जारी की। इसका विशेष रूप से देश के मध्य और पश्चिमी भागों पर प्रभाव पड़ेगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक वरुंचुअल समाचार सम्मेलन में कहा, अप्रैल-जून की अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य चार से आठ

दिनों की तुलना में 10 से 20 दिन हीट-वेव रिकॉर्ड हो सकते हैं। लगभग 97 करोड़ पात्र मतदाताओं के साथ, न केवल मतदान प्रतिशत को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, बल्कि चिलचिलाती गर्मी के बीच दिव्यांग और बुजुर्ग आबादी जैसे कमजोर मतदाताओं की भलाई के बारे में भी चिंताएं पैदा होती हैं। जैसा कि चुनाव प्रचार पहले ही शुरू हो चुका है, कई राजनीतिक दल इस बात पर भी रणनीति बना रहे हैं कि आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार गर्मी असहनीय होने की स्थिति में मतदाताओं को वोट डालने के लिए चुनावी बूथ तक कैसे लाया जाए। एक राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार अभियान रणनीतिकार ने कहा, दिव्यांगों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित, लेकिन मतदान केंद्र पर वोट देने के अपने (शेष पेज 9)

तमिलनाडु में छाया कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा

कुमार चेलप्पन | चेन्नई

भारत और श्रीलंका के बीच कच्चातीवू द्वीप मुद्दा सोमवार तक विवाद चरम बिंदु पर पहुंच गया। जहां द्रमुक और कांग्रेस ने श्रीलंका से द्वीप को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। वहीं विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मीडिया को एक ब्रीफिंग में बताया कि एम करुणानिधि के नेतृत्व वाली तत्कालीन द्रमुक सरकार को स्थानांतरण के सभी चरणों के दौरान भारत सरकार द्वारा स्थानांतरण सौदे के बारे में जानकारी दी गई थी। कच्चातीवू का मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में छाया हुआ है क्योंकि द्रमुक ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में उल्लेख किया है कि केंद्र सरकार को श्रीलंका से इस द्वीप को पुनः प्राप्त करना चाहिए। घोषणापत्र में 2014 से देश पर शासन करने के बावजूद इस द्वीप को पुनः प्राप्त करने में विफलता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को भी दोषी ठहराया गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से पता चलता है कि द्रमुक और उसके अध्यक्ष एम के स्टालिन इस मुद्दे को काफी उछाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में राजस्थान में अपने अभियान भाषणों के दौरान कच्चातीवू मुद्दे में जो कुछ हुआ उसका स्पष्ट विवरण दिया है। लेकिन 2016 में तमिलनाडु विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा दिया गया भाषण सोमवार तक वायरल होने से द्रमुक और कांग्रेस को झटका लगा।

लगातार बढ़ती चुनावी गर्मी में राहत का साधन बना गमछा

बिस्वजीत बनर्जी | लखनऊ

जैसे-जैसे विभिन्न भारतीय राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ रहा है, एक सर्वोत्कृष्ट सहायक वस्तु ने राजनीतिक क्षेत्र के क्षेत्र में मुख्य स्थान ले लिया है और वह है साधारण गमछा या सूती दुपट्टा। उत्तर प्रदेश के टांडा और बिहार के भागलपुर जैसे क्षेत्रों से निकले, ये बहुमुखी सूती कपड़े न केवल चेहरे को पोंछने के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि गंगा क्षेत्र के राजनेताओं के लिए बोल्ट फैशन स्टेटमेंट भी बना रहे हैं। टांडा और भागलपुर राजनीतिक दलों के लिए गमछा के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में

उभरे हैं, जिनकी कीमतें 25 रुपये से 40 रुपये प्रति पीस तक हैं। असंख्य आकृतियों, आकारों और रंगों में उपलब्ध, ये गमछा विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गमछा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, टांडा और भागलपुर में बुनकरों को उत्पादनक प्रतिशता मिल रही है। अकेले टांडा में, 100 से अधिक छोटी इकाइयाँ 5000 से अधिक बुनकरों को काम पर लगाती हैं और केवल दो महीनों में लगभग 50 लाख रुपये के ऑर्डर पूरे करती हैं। इसी तरह, भागलपुर में, 3000 से अधिक बुनकर गमछा बनाने में लगे हुए हैं, प्रत्येक



बुनकर प्रतिदिन औसतन 24 पीस का उत्पादन करता है और प्रति दिन 200-300 रुपये कमाता है। इन बुनकरों को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,

छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के टांडा, अकबरपुर में गुलशन खादी के मालिक मेहरान हसन अंसारी ने चुनाव के दौरान मांग में तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, कई राजनीतिक दल अपने समर्थकों को गमछा बांटते हैं जो न केवल उन्हें पहचान देता है बल्कि बेहद जरूरी प्रचार भी देता है। विभिन्न राजनीतिक दल अलग-अलग रंगों से जुड़े हैं। केसरिया रंग भाजपा के लिए, पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के लिए, नीला रंग बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के लिए, सफेद रंग कांग्रेस के लिए और हरा रंग

राजद के लिए है। राजद अपने चुनाव चिन्ह लालटेन को भी हरे गमछे पर सफेद रंग में प्रदर्शित करना पसंद करता है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ. एहंमद पांडेय के मुताबिक राजनीतिक प्रतीक से आगे गमछा चिलचिलाती गर्मी से बचाव में बेहद कारगर है। गमछा से सिर ठंढकने से लू से बचने की 60 फीसदी संभावना है। लिहाजा गर्मियों में बाहर निकलते समय सिर पर टोपी या गमछा रखना चाहिए। कई राज्यों द्वारा लाखों भगवा गमछा के ऑर्डर दिए जाने से, पिछले वर्ष की तुलना में भागलपुरी गमछा की मांग 30 फीसदी बढ़ गई है। इसके अलावा, महिला नेता और कार्यकर्ता

चुनावी उत्साह को दर्शाते हुए विभिन्न रंगों के भागलपुरी सूट और दुपट्टे चुन रही हैं। हरे गमछा और टोपी के ऑर्डर भी बाढ़ आ गए हैं, प्रत्येक की कीमत क्रमशः 100-120 रुपये और 80-120 रुपये के बीच है। विशेष रूप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान खुद डिजाइनर गमछा पहनते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माला के बजाय खादी गमछा पसंद करते हैं। गमछा की मांग में वृद्धि 2019 के चुनावों की याद दिलाती है जब खादी गमछा के ऑर्डर 3,215 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड उंचाई तक पहुंच गई थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 29 फीसदी की वृद्धि थी। (शेष पेज 9)

आप कितने भी दल जुटा लो, आएंगे तो मोदी ही: शाह

भाषा। जोधपुर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर इंडिया गठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा, कितने भी दल इकट्ठा कर लो आएगा तो मोदी ही आएगा। प्रदेश के जोधपुर में गृह मंत्री जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वह सलाखों के पीछे जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और उनके अगले कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। शाह ने कहा, ए लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं… राहुल बाबा आपको दादी ने आपातकाल में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था…राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था…आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा, ए जो कुनवा इकट्ठा हुआ है… कल उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाओ। व्यूं भई क्या हो

गया है लोकतंत्र को। इस देश की जनता वोट डालने वाली है। तय करेगी। आप काहो को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भई मुझे बताओ 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने कल की रैली में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारी बहुमत से चुनाव जीतकर संविधान खत्म किया जा सके। शाह ने इस पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा, .. राहुल बाबा सुन लो क्यूं फरियाद कर रहे हो हमने 2014 में भी किया 2019 में भी किया। कहकर हम चुनाव लड़े थे कि जो भ्रष्टाचार करेगा वह जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। शाह ने कहा, मित्रों ए लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं… कितने भी दल इकट्ठा कर लो आएगा तो मोदी ही आएगा। केंद्र सरकार द्वारा किए काम गिनाते हुए शाह ने कहा कि हमने बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम मोदी जी ने किया है। हर दिन 37 स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का काम मोदी जी ने किया है। भारत में हर दिन 16 हजार करोड़ रुपए के यूपीआई टूंगैजेशन होते हैं। भारत में हर दिन 14 किमी रोड बनती है। भारत में हर दिन गैस के 50 हजार कनेक्शन देने का काम मोदी जी ने किया है। हर सेकंड एक घर को नल



का कनेक्शन देने का काम भी मोदी जी और भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा, हमने देश को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध किया है, और इसके साथ-साथ

हमने ढेर सारे वादे जो भाजपा की स्थापना से करे हैं उन सारे वादों को मोदी जी ने इन साल में पूरा करने का काम किया है। शाह ने कहा, मोदी जी को तीसरी

बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, भारत दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

उन्होंने कहा, हमने डेढ़ सौ साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदल दिए सौ साल पुरानी संसद बदली हमने नक्सलवाद व उग्रवाद को उखाड़ फेंकने का काम किया। शाह ने कहा, इसलिए 2014 में 55 फीसदी वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत बढ़कर 61 प्रतिशत हुआ और फिर सभी 25 सीटें भाजपा को मिली। अब मोदी जी फिर से आए हैं, इस बार 70 प्रतिशत वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्टिक लगानी है। उन्होंने कहा, इस लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। 400 से ज्यादा सीटें रागज जीतेगा और 370 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा ए तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं[8230].. पांच साल के अंतर राजस्थान में जगह जगह पर बहुमत समाज के धार्मिक स्थानों पर हमला हुआ[8230] कन्हैयालाल को मार दिया गया.. कई सारे लोगों को मार दिया गया .. ए तुष्टिकरण करने वाले लोग है हमारा मत है न्यए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को वापस ले लिया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, हमने 150 साल पुराने कानून बदल दिए, 100 साल पुरानी संसद बांग दी।

पश्चिम बंगाल में आए तूफान में मृतकसंख्या बढ़कर पांच

जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में रविवार को आए तूफान के कारण मरने की वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। इस तूफान में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिला मुख्यालय शहर के अधिकतर हिस्सों और पड़ोसी मैनागुड़ी के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने से कई झोपड़ियों और मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। ममता ने रविवार देर रात जिले का दौरा किया और लोगों को प्रशासन की ओर से हर्ससंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, अब तक, हमारे पास पांच लोगों की मौत होने की खबर है। घायलों की संख्या काफी अधिक है। मैंने घायलों और तूफान में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात की। राज्य प्रशासन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हर्ससंभव कोशिश करेगा। मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर ममता ने कहा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। आपको जिला प्रशासन से बात करनी होगी। तूफान के कारण राजारहाट, बार्निश, बकाली, जोरपाकड़ी, माधबडंगा और सपतीवारी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं एवं कई एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने रविवार रात अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने तूफान में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों से भी बात की और उन्हें हर प्रकार की सहायता मुहैया करए जाने का आश्वासन दिया। बनर्जी ने कहा, यह एक आपदा है, एक आपातकालीन स्थिति है। मैंने मृतकों के परिवारों और उन लोगों से मुलाकात की जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मैं बचाव अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दूंगी। हम लोगों के साथ हैं और उनके इलाज एवं मकानों के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। ममता तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ जलपाईगुड़ी चिकित्सकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल गईं और उन्होंने रास्ते में वीडियो कॉल के माध्यम से जिलों के अन्य हिस्सों के रहत शिविरों में मौजूद लोगों से भी बात की।

प्राथमिकियों के जोड़ने के लिए रिट क्षेत्राधिकार के तहत अनुरोध पर न्यायालय का उदयनिधि से सवाल

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन से सोमवार को पूछा कि वह सनातन धर्म को खत्म करे वाली अपनी टिप्पणी को लेकर दर्ज कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की याचिका रिट क्षेत्राधिकार के तहत शीर्ष अदालत में कैसे दायर कर सकते हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता की पीठ ने मंत्री से कहा कि वह आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 406 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सकते थे, जिसमें आपराधिक मामलों को हस्तांतरित करने का प्रावधान है, लेकिन रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, देखिए, कुछ मामलों में संज्ञान लिया गया है और समन जारी किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के तहत न्यायिक कार्यवाही नहीं कर सकता। न्यायालय ने उदयनिधि स्टालिन को कानूनी समस्याओं के मद्देनजर अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और छह माई से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। तमिलनाडु के मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह टिप्पणी करने का मकसद राजनीतिक युद्धोपेय करना नहीं था क्योंकि यह केवल 30 से 40 लोगों की सभा थी। न्यायमूर्ति दत्ता ने उन मामलों का जिक्र किया, जिनका प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए उदयनिधि स्टालिन ने हवाला दिया है। इनमें पत्रकार और राजनीतिक लोगों के मामले भी शामिल हैं।

पेज 1 का शेष

केजरीवाल ने...

जो वैसे भी दिल्ली के सीएम के काम के लिए है, न कि पार्टी के लिए। केजरीवाल जवाब देने से बचते रहे। यह सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों की अनभिज्ञता का दावा करके कहा गया है। याचिका में रेखांकित किया गया कि नायर पार्टी में कोई छोटे-मोटे स्वयंसेवक नहीं थे, बल्कि मीडिया और संचार के प्रमुख थे। गिरफ्तार और (केजरीवाल) ने उसे दिखाए गए डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड भी नहीं बताए हैं जो साक्ष्य संग्रह को बाधित करता है और उसके असहयोग को भी दर्शाता है। आवेदन में कहा गया है कि केजरीवाल को शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और यहां तक कि दिनेश अरोड़ा और अभिषेक बोइनपल्ली जैसे बिचौलियों सहित शराब व्यवसाय में शामिल अन्य सह-आरोपियों के साथ नायर की 10 से अधिक बैठकों के सबूत दिखाए गए थे। गिरफ्तार व्यक्ति को यह समझाने के लिए

कहा गया था कि नायर किस अधिकार के साथ इन बैठकों में शामिल हुआ था, गिरफ्तार व्यक्ति ने इन व्यक्तियों के बारे में अनभिज्ञता का दावा करके सवालों को टाल दिया और यह स्पष्ट है कि नायर जैसा वरिष्ठ पदाधिकारी जिसने गिरफ्तार व्यक्ति के साथ चर्चा करके काम किया है, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। रिमांड आवेदन में कहा गया, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन साजिशों या बैठकों का अंतिम लाभ आप को गोवा बुनियाद अभियान में मिला। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल को लगभग 45 करोड़ रुपये के हवाला हस्तांतरण के सबूत दिखाए गए थे, जिसकी पृष्ठि सीडीआर स्थानों, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, गोवा में सबूतों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाकर उससे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड भी नहीं बताए हैं जो साक्ष्य संग्रह को बाधित करता है और उसके असहयोग को भी दर्शाता है। आवेदन में कहा गया है कि केजरीवाल ने आप के गिरफ्तार व्यक्ति ने अनभिज्ञता का दावा किया, भले ही इन फंडों का लाभार्थी आप है, जिसका नेतृत्व वह कर रहा है। आवेदन में कहा गया है कि केजरीवाल ने आप के अन्य सदस्यों के बारे में गलत और विपरीत

सबूत मुहैया कराए। इसमें कहा गया है कि आप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एन डी गुप्ता ने कहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने राज्य चुनाव प्रभारी या प्रभारी नियुक्त किया था, जो चुनाव अभियानों से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता था। दुर्गेश पाठक को गोवा चुनाव के लिए प्रभारी चुना गया। हालांकि, केजरीवाल ने कहा कि यह राजनीतिक मामलों की समिति (पीएस) है जिसने राज्य चुनाव आगे बढ्ना चाहिए। इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्र को डीडी ने गिरफ्तार किया था।

भारतीयों..

एक राजतूत के लिए। हालाँकि, सामान्य प्रतीक्षा समय वास्तव में 200 दिनों से कम है। हमारे मौजूदा संसार्थनों के साथ यह चुनौतीपूर्ण है।

लोस चुनाव...

अधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक लोगों को चिलचिलाती गर्मी के दौरान अधिकारश राज्यों में कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है, जहां उच्च

ल् चलने की भविष्यवाणी की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार, पीडब्ल्यूडी के तहत लगभग 88.35 लाख मतदाता हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मतदाताओं को गर्मी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें पहले से जारी विभिन्न सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि, रिजिजू ने विश्वास जताया, भारत में चुनाव के दौरान लोग चुनावी रैलियों, बैठकों के लिए निकलेंगे... पूरे देश में भारी गतिविधियां होंगी। आईएमडी प्रमुख के अनुसार, इस अवधि में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान होने का अनुमान है, मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सबसे गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। विभिन्न अध्ययनों ने पहले ही चिंता व्यक्त की है कि इस गर्मी में चुनावी प्रक्रिया के दौरान गर्मी को लहरें पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना है। भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने आगामी गर्मी के मौसम के दौरान मतदाताओं और मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय के रूप में पहले से ही हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी है। इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीओ) को लू के प्रभाव

को कम करने के लिए आवश्यक उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। आयोग ने श्रेणी के तहत लगभग 88.35 लाख मतदाता हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मतदाताओं को गर्मी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें पहले से जारी विभिन्न सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि, रिजिजू ने विश्वास जताया, भारत में चुनाव के दौरान लोग चुनावी रैलियों, बैठकों के लिए निकलेंगे... पूरे देश में भारी गतिविधियां होंगी। आईएमडी प्रमुख के अनुसार, इस अवधि में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान होने का अनुमान है, मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सबसे गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। विभिन्न अध्ययनों ने पहले ही चिंता व्यक्त की है कि इस गर्मी में चुनावी प्रक्रिया के दौरान गर्मी को लहरें पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना है। भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने आगामी गर्मी के मौसम के दौरान मतदाताओं और मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय के रूप में पहले से ही हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी है। इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीओ) को लू के प्रभाव

तमिलनाडु की.. का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि करुणानिधि, जो 2008 में मुख्यमंत्री थे, उनके नोटिस के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करने में अनिच्छुक थे। जयललिता ने कहा था, मुझे अधिकारियों ने बताया कि करुणानिधि ने उनसे केंद्र द्वारा हलफनामा दायर करने तक इंतजार करने और फिर केंद्र की बात मानते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। करुणानिधि या द्रमुक को श्रीलंका से द्वीप वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब एक द्रमुक सदस्य औचित्य का सवाल लेकर उठे, तो अम्मा ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर द्रमुक कच्चातौंवू के बारे में बहुत ज्यादा बोलेंगी, तो उन्हें कुछ और खुलासे करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

लगतातर बढ़ती

जैसा कि भारत चिलचिलाती गर्मी के तापमान और गर्म राजनीतिक अभियानों के लिए तैयार है, गमख सिर्फ एक हलफनाहारिक सहायक नहीं बल्कि अभियान पथ पर राजनीतिक पहचान और शैली का प्रतीक बना हुआ है।

न्यायालय ने प्रयागराज स्थित कृषि विवि के कुलपति को जमानत दी

धर्मांतरण मामला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश स्थित सैम हिंगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय (शुआर्ट्स) के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल को सोमवार को अंतरिम जमानत देने की पुष्टि की। अदालत ने यह राहत लाल को कथित धर्मांतरण सहित दो आपराधिक मामलों में दी है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या हमें मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कुछ चिंता नहीं है। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने लाल की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रयागराज के नवाबगंज और नैनी पुलिस थानों में दर्ज दो प्राथमिकियों के संबंध में उन्हें चार मार्च को अंतरिम जमानत दे दी थी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमारे द्वारा चार मार्च को पारित अंतरिम जमानत आदेश की हम पुष्टि करते हैं।



शीर्ष अदालत ने कहा कि लाल को एक प्राथमिकी में लॉबिज जांच में पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। प्रधान न्यायधीश ने मौखिक टिप्पणी

की, हम महसूस करते हैं कि राज्य (पुलिस) इस मामले में अतिरिक्त रचि ले रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की एक अलग अर्जी को

दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत के लगी फटकार

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को फटकार लगाई है। घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और श्रीनेत ने अभिनेत्री कंगना रतौत के खिलाफ आपत्तजनक टिप्पणी की थी। आयोग ने कहा कि दोनों नेताओं ने निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला किया और यह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है।इन्हें आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।सोमवार से आयोग द्वारा इन दोनों नेताओं के चुनाव संबंधी संवाद पर विशेष और अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। आयोग के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में संवाद करते समय सावधानी बरतने और ऐसी किसी भी अपमानजनक टिप्पणी और आचार संहिता के दिशानिर्देशों के उल्लंघन से बचने के लिए निर्देशों को उल्लंघन को संवेदनशील बनाने के वास्ते चेतावनी नोटिस की एक प्रति उनके संबंधित पार्टी प्रमुखों को भी भेजी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्षों से आयोग ने कहा, आप कृपा चुनाव अभियान में शामिल सभी पार्टी पदाधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र में बातचीत के लिए विशेष सलाह जारी करें कि वे इस तरह

निर्वाचन आयोग ने अपमानजनक टिप्पणियों के लिए की कार्रवाई

का उल्लंघन न करें, आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करें ताकि प्रतिक्रिया में इस तरह की टिप्पणियां नहीं हों। श्रीनेत के इंट्राग्राम अकाउंट से सोशल मीडिया मंच पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रतौत के खिलाफ एक विवादास्पद टिप्पणी पोस्ट की गई थी। कंगना को भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। विवाद के बाद श्रीनेत ने अपने सभी सोशल अकाउंट्स से विवादास्पद टिप्पणियों को हटा दिया। उनका कहना यह कि उनके अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और यह टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की गई। घोष एक वीडियो में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक बनाते हुए नजर आए थे। बाद में उन्होंने अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांग ली। भाजपा ने श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, वहीं टीएमसी ने घोष के खिलाफ चुनाव आयोग से संपर्क किया था।

आदि कैलाश, ओम पर्वत के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू

पिथौरागढ़। उत्तराखंड केपिथौरागढ़ जिले मे स्थित प्रसिद्ध धार्मिकपर्यटकरस्थलों आदि कैलाश तथा ओमपर्वत के लिए सोमवार को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई। अधिकारियों ने यहा बताया कि इस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत पिथौरागढ़ के संसुत्रा गजिस्टेट आश्री मिश्रा ने मैनी सैणी हवाई अड्डे से की। उन्होने बताया कि उत्तराखंड सरकार ही हेली दर्शन योजना के तहत एमआई17 हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओ को हवाई अड्डे से व्यास घाटी क्षेत्र मे आदि कैलाश और ओम पर्वत तक ले जाएगा और घोरटियों केउपर कुछ देर चक्कर लगाने केबाद वापस हवाई अड्डेपहुँचाएगा। पिथौरागढ़ केजिला पर्यटन अधिकारी र्चिंतींदर आर्य ने बताया किस्वर्इ वन एरक्षेत्र द्वारा संसाहित दो घंटे के इस दौरे की लागत प्रति व्यक्ति 40 हजार र्पाए होगी और इस पर जीएसटी अलग से देय होगा। उन्होंने बताया किआदि कैलाश और ओम पर्वत की इस उद्घाटन उड़ान मे 16 श्रद्धालुओ ने यात्रा की। पिछ्लाल इस योजना के प्रयोग के तौर पर चलाया जा रहा है। आर्य को ष्य, यगार यह प्रयोग सफल हुआ तो अगले माह से यह उड़ान श्रद्धालुओ को सप्ताह मे पांच दिन उपलब्ध रहेगी। मिश्रा ने बताया कियह योजना राज्य केलिए एकउपनिधि है और इससे आदि कैलाश क्षेत्र को बढ़ावा देने मे मदद मिलेगी। उन्होने बताया किपिछले साल अक्ूबर मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलाश व दर्शन किए जाने से पर्यटकों और श्रद्धालुओ मे इन धार्मिकपर्यटन स्थलों की लोकप्रियता मे जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।



पिथौरागढ़

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए 30 नाम जारी किए

भाषा। बीजिंग

अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करने की चीन की हालिया कोशिशों के बीच बीजिंग ने भारतीय राज्य में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की है।

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने की कवायद को भारत खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि यह राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रखने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा।

सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को बताया कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की। चीन अरुणाचल प्रदेश

को जंगनान कहता है और दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में इस राज्य पर अपना दावा करता है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर क्षेत्र के लिए 30 अतिरिक्त नाम पोस्ट किए रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार, इस घोषणा के क्रियान्वयन में कहा गया है कि चीन के क्षेत्रीय दावों और संप्रभुता अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकने वाले विदेशी भाषाओं में रखे गए, स्थानों के नामों को बिना प्राधिकार के सीधे उद्धृत या अनुवादित नहीं किया जाएगा।

चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में छह स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में जारी की थी,

जबकि 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी। इसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नामों के साथ एक और सूची जारी की गई थी।

अरुणाचल प्रदेश पर दावों को लेकर चीन की हालिया बयानबाजी उस समय शुरू हुई जब उसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर एक सवाल के जवाब में कहा था, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। मेरा मतलब है कि चीन ने दावा किया है, इसने अपने दावे को दोहराया है। ए दावे शुरू से बेतुके हैं और आज भी बेतुके ही हैं।

उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हम इस पर बहुत स्पष्ट रहे हैं और हमारा एक समान स्वरु रहा है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह ऐसी चीज है, जो वर्तमान में जारी सीमा वार्ता का हिस्सा है। चीन

को 23 मार्च को बेतुका करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि यह सीमांत राज्य भारत का स्वाभाविक हिस्सा है।

उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूस) के साउथ एशियन स्टडीज इंस्टीट्यूट में एक व्याख्यान देने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर एक सवाल के जवाब में कहा था, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। मेरा मतलब है कि चीन ने दावा किया है, इसने अपने दावे को दोहराया है। ए दावे शुरू से बेतुके हैं और आज भी बेतुके ही हैं।

उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हम इस पर बहुत स्पष्ट रहे हैं और हमारा एक समान स्वरु रहा है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह ऐसी चीज है, जो वर्तमान में जारी सीमा वार्ता का हिस्सा है। चीन

अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता देने वाले अमेरिका के बयान से भी नाराज है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पेले ने नौ मार्च को कहा था, अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य या असेन्य घुसपैठ या अतिक्रमण के जरिए क्षेत्रीय दावे करने के किसी भी एकांतरका प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं।

चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि चीन-भारत सीमा मुद्दा दोनों देशों के बीच का मामला है और इसका अमेरिका से कोई लेना-देना नहीं है।

तोशाखाना मामले में इमरान, उनकी पत्नी की सजा निलंबित

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तब एक बड़ी राहत मिली जब एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दो गई 14 साल की सजा सोमवार को निलंबित कर दी।

देश में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी। दोनों ने सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्य पीठ ने मामले की सुनवाई की।

सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में दंपति की सजा को निलंबित करके और उन्हें जमानत देकर अस्थाई राहत दी। हालांकि अदालत ने घोषणा की कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी।

हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और उनकी पत्नी को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और हो सकता है कि उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाए।

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है। सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया।

तीस जनवरी को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मामले में खान को दोषी ठहराया गया था। इससे पहले, उन्हें अगस्त 2023 में तोशाखाना के एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।



तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।

सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया।

तीस जनवरी को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मामले में खान को दोषी ठहराया गया था। इससे पहले, उन्हें अगस्त 2023 में तोशाखाना के एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

तुर्किए में स्थानीय चुनाव में एर्दोआन को झटका

एपी। अंकारा

तुर्किए की मुख्य विपक्ष पार्टी ने रविवार को हुए स्थानीय चुनावों में अहम शहरों में अपनी पकड़ कायम रखी तथा अन्य स्थानों पर बड़ी बढ़त हासिल की।

शुक्राती नतीजे राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के लिए झटका हैं जो इन शहरी इलाकों में फिर से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में थे।

सरकारी प्रसारणकर्ता टीआरटी के मुताबिक, अब तक करीब 60 फीसदी मतों की गणना की जा चुकी है और तुर्किए के सबसे बड़े शहर एवं

आर्थिक केंद्र इस्तांबुल में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के मौजूदा मेयर अकस इमामोगलु बहाल बनाए गए हैं। वहीं, राजधानी अंकारा में मेयर मंसूर यावस बड़े अंतर से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। टीआरटी के मुताबिक, सीएचपी तुर्किए के 81 प्रांत में से 36 पर आगे है।

चुनाव को राष्ट्रपति एर्दोआन की लोकप्रियता के पैमाने के तौर पर देखा जा रहा था। वह इन अहम शहरी क्षेत्रों में अपनी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश में थे। पांच साल पहले उलनका पार्टी विपक्षी दल से हार गई थी।

यह नतीजे विपक्ष के लिए संजीवनी हैं जो पिछले साल हुए राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव में एर्दोआन के हाथों हार के बाद विभाजित हो गया था और उसका मनोबल टूट गया था।

सीएचपी नेता ओज़गुर ओज़ेले ने उत्साही समर्थकों की भीड़ से कहा, 'मतदाताओं ने तुर्किए में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा, 'आज, मतदाताओं ने तुर्किए में 22 साल पुरानी तस्वीर को बदलने और हमारे देश में एक नए राजनीतिक माहौल का दूर खोलने का फैसला किया।'



अंकारा में अपने पार्टी मुख्यालय में समर्थकों का अभिवादन करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता रजब तैयब एर्दोआन और उनकी पत्नी एमीने एर्दोआन

अमेरिका में भाजपा समर्थकों ने 20 शहरों में निकाली रैली

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (ओएफबीजेपी-यूएसए) ने देश के 20 अलग-अलग शहरों में

भारतीय-अमेरिकी समुदाय मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और राजग को 400 सीट से अधिक सीट पर जीतता देखने के लिए बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भारतीय

आयोजित कर रैलियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया है।

अमेरिका की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में सिख समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री

गाजा के मुख्य अस्पताल से हटी इजराइली सेना

एपी। देर अल-बला (गाजा पट्टी)

इजराइली सेना ने दो हफ्तों तक किए गए हमलों के बाद गाजा के मुख्य अस्पताल से अपने सैनिकों को हटा लिया और अपने पीछे तबाही के बड़े निशान छोड़ दिए हैं। फलस्तीनी निवासियों ने यह जानकारी दी।

इजराइली सैनिकों को हटाए जाने के बाद सोमवार को सुबह सैकड़ों लोग शिफा अस्पताल और आसपास के इलाकों में लौटे जहां उन्हें अस्पताल के अंदर और बाहर शव पड़े मिले।

इजराइली सेना ने इस हमले को करीब छह महीने से चल रहे युद्ध के सबसे सफल अभियान में से एक बताया और कहा कि उसने सैकड़ों हमास और अन्य आतंकवादियों को मार गिराया तथा कुछ अहम खुफिया दस्तावेज भी जब्त किए।

इजराइली सेना हटाए जाने के बाद इलाके में लौटे मोहम्मद महदी ने घटनास्थल के दृश्य को पूरी तबाही बताया। उन्होंने कहा कि कई इमारतें जला दी गईं। उन्होंने इलाके में छह शवों की गिनती की। इनमें से दो शव अस्पताल परिसर में पड़े थे।

एक अन्य निवासी याहिया अबू औफ ने कहा कि अस्पताल में मरीज, चिकित्सा कर्मी तथा विस्थापित लोग मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कई मरीजों को नजदीकी अहली हॉस्पिटल ले जाया गया है।

पाकिस्तान में मारे गए पांच चीनी नागरिकों के शव पाक सैन्य विमान से वुहान पहुंचाए गए

भाषा। बीजिंग

पाकिस्तान में आत्मघाती बम हमले में मारे गए पांच चीन के पांच कर्मियों के शवों को सोमवार को एक विशेष पाकिस्तानी सैन्य विमान से आज चीन वापस लाए गए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी नागरिकों पर जानलेवा आतंकी हमले के मामले में संयुक्त जांच का आदेश दिया था।

बीजिंग ने इस्लामाबाद पर जोर दिया था कि हमलावरों की खोजबीन तेज की जाए और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। वांग ने कहा कि जो कुछ हुआ, उसकी जांच करने, अपराधियों और हमले के पीछे के लोगों को न्याय के कठपंते में लाने और पाकिस्तान में चीनी कर्मियों की परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने में चीन पूरी दृढ़ता और प्रयास के साथ पाकिस्तान का समर्थन करता है।

दासू जलविद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीनी कर्मियों पर आत्मघाती बम हमले का यह दूसरा मामला है। पाकिस्तान की सरकारी एपीपी एजेंसी ने बताया कि विशेष विमान शवों को चीन के वुहान शहर लेकर आया।

पाकिस्तान के संघीय प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास मंत्री चौधरी सालिक हुसैन भी चीन के विदेश मंत्रालय के

प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां संवाददाताओं से कहा, पाकिस्तान में दासू परियोजना पर आतंकवादी हमले में मारे गए पांच चीनी नागरिकों के शव पाकिस्तानी सैन्य विमान से आज चीन वापस लाए गए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी नागरिकों पर जानलेवा आतंकी हमले के मामले में संयुक्त जांच का आदेश दिया था।

बीजिंग ने इस्लामाबाद पर जोर दिया था कि हमलावरों की खोजबीन तेज की जाए और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। वांग ने कहा कि जो कुछ हुआ, उसकी जांच करने, अपराधियों और हमले के पीछे के लोगों को न्याय के कठपंते में लाने और पाकिस्तान में चीनी कर्मियों की परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने में चीन पूरी दृढ़ता और प्रयास के साथ पाकिस्तान का समर्थन करता है।

दासू जलविद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीनी कर्मियों पर आत्मघाती बम हमले का यह दूसरा मामला है। पाकिस्तान की सरकारी एपीपी एजेंसी ने बताया कि विशेष विमान शवों को चीन के वुहान शहर लेकर आया।

पाकिस्तान के संघीय प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास मंत्री चौधरी सालिक हुसैन भी

नेपाल के विकास के लिए चीन के साथ हुई चर्चा : उप प्रधानमंत्री नारायण

भाषा। काठमांडू

नेपाल के उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने सोमवार को यहां कहा कि उनके देश और चीन ने बीजिंग समर्थित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) परियोजनाओं के कार्यान्वयन योजना के साथ आगे बढ़ने में प्रगति की है।

श्रेष्ठ ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान बीआरआई कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से जुड़े विषयों पर चीन के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

श्रेष्ठ ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान बीआरआई कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से जुड़े विषयों पर चीन के अधिकारियों के साथ चर्चा की।



के दौरान बातचीत आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि बीआरआई के तहत नेपाल अपनी पसंद के अनुसार विकास परियोजनाओं का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि बीआरआई के तहत अनुदान सहायता को प्राथमिकता देते हैं लेकिन अनुदान और ऋण सहित

दोनों विकल्प खुले हैं और कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने के बाद इस विषय पर चर्चा की जाएगी। नेपाल और चीन ने बीआरआई समझौते पर सात साल पहले हस्ताक्षर किए थे।

अपनी यात्रा के दौरान, श्रेष्ठ ने चीनी अधिकारियों से नेपाल के रास्ते तिब्बत स्थित कैलाश-मानसरोवर जाने वाले विदेशी पर्यटकों पर बीजिंग द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए भी कहा। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने काठमांडू और चीन के दूतों के बीच लेने वाले लोग पहले बस सेवा फिर से शुरू करने पर सकारात्मक रुख जाहिर किया है।

उन्होंने कहा, हमने नेपाल-तिब्बत-छोंगचिंग-सिचुआन के बीच विकास गलियारे के निर्माण से संबंधित विषयों पर सकारात्मक चर्चा की।

लाल सागर और यमन में हूती झेन नष्ट किए: अमेरिकी सेना

एपी। काहिरा

अमेरिकी बलों ने युद्धग्रस्त यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में एक झेन और लाल सागर में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के उभर एक अन्य झेन को नष्ट कर दिया। ईरान समर्थित विद्रोहियों और अमेरिका के बीच कई महीनों से बढ़ रहे तनाव के बीच यह ताजा घटना हुई है। अमेरिकी ने कहा कि नष्ट किए गए झेन क्षेत्र में अमेरिकी एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बलों के बीच तनाव कम हो चुका है।

अमेरिकी, गठबंधन और वाणिज्यिक पोतों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ए कार्रवाई आवश्यक है।

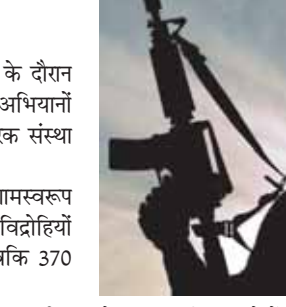
पाकिस्तान: साल की पहली तिमाही में आतंकी हमलों, आतंकवाद रोधी अभियान के 245 मामले सामने आए

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान में 2024 की पहली तिमाही के दौरान आतंकवादी हमलों और आतंकवाद रोधी अभियानों के 245 मामले सामने आए। एक विचारक संस्था की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

इसमें कहा गया कि इसके परिणामस्वरूप असेन्य नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और विद्रोहियों समेत कुल 432 लोगों की मौत हुई जबकि 370 लोग घायल हुए।

सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिम्बोरिटी स्टडीज (सीआरएसएस) द्वारा जारी सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान कुल मौतों में से 92 प्रतिशत अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा (केपी) और बलूचिस्तान प्रांत में हुई जबकि 86 प्रतिशत हमले (आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं और सुरक्षा बलों के अभियान समेत) भी इस इलाके में हुए। अलग-अलग बात करें तो 2024 की पहली तिमाही में सभी मौतों में 51 प्रतिशत खैबर पख्तूनख्वा में और 41 प्रतिशत बलूचिस्तान में हुई। आंकड़े बताते हैं कि शेष क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत थे, जहां मौत के सभी मामलों में से



शेष आठ प्रतिशत लोगों की जान गई। आतंकवादी संगठनों ने 2024 की पहली तिमाही में आतंकवाद के कारण हुई कुल मौत में से 20 प्रतिशत से भी कम की जिम्मेदारी ली है। गुल बहादुर समूह से संबद्ध जब्त अंसार अल-महदी खुरसान (जेएएमके) नामक एक नया आतंकवादी समूह उभरा है। आतंकवाद और आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान हताहतों की संख्या के अलावा, देश में सरकारी, राजनेताओं और निजी और सुरक्षा संपत्तियों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की 64 घटनाएं हुईं। पहली तिमाही में बलूचिस्तान में हिंसा में 96

प्रतिशत की चौकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई जब 2023 की अंतिम तिमाही में जान गंवाने वाले 91 लोगों के मुकाबले 2024 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा बढ़कर 178 हो गया।

सिंध में हिंसा में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि मरने वालों की संख्या बहुत कम थी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हिंसा में क्रमशः 24 प्रतिशत, 85 प्रतिशत और 65 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान गिलगित-बाल्टिस्तान में हिंसा में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, प्रांत के गृह मंत्री ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा हमलों की आशंका को लेकर 31 मार्च, 2024 को एक आतंकी खतरे की चेतावनी जारी की। चालू वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 200 आतंकवादी हमलों में 65 प्रतिशत (281) मौत नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की हुईं। वहीं 48 आतंकवाद विरोधी अभियानों में केवल 35 प्रतिशत (151) मौतें अपराधियों की हुईं। कुल 156 नागरिकों (36 प्रतिशत) को जान गंवानी पड़ी जो मृतकों की किसी भी अन्य श्रेणी से अधिक है।

